developmental needs. Therefore, a special dispensation should be made for the Special Category States to enable them to narrow down the regional disparities and to catch up with the level of development in the rest of the country.

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): महोदय, मैंने दिनांक 8 जून को एयर इंडिया के बारे में अपना वक्तव्य रखा था लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। दिनांक 2 जुलाई को मैंने स्वयं सिविल एविएशन मंत्री जी से मुलाकात की और रिक्वेस्ट की और आज दोबारा यह मामला उठा रहा हूं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एयर इंडिया का व्यवहार ठीक नहीं है। चैन्नई से पोर्टब्लेयर और कोलकाता से पोर्टब्लेयर तक एयर फेयर की रेंज 17,000 से 24,000 रुपए है, यह हाइएस्ट इंडियन रूट्स में है। अगर कम्पेयर किया जाए तो दिल्ली-गुवाहटी, 3 घंटे 15 मिनट की एयर जर्नी का एयर फेयर 6500 है जबकि चैन्नई से पोर्टब्लेयर और कोलकाता से पोर्टब्लेयर, दो घंटे की एयर जर्नी का एयर फेयर 17,000 से 24,000 रुपए है। इससे मुश्किल हो रही है। द्वीप के जो लोग हैं उन्हें टिकट खरीदने में मुश्किल आ रही है, खास तौर से जो टूरिज्म इंडस्ट्री डेवलप की थी वह इससे सफर हो रही है। खासकर सिंगापुर, कोलम्बो रिटर्न जर्नी टिकट 13 हजार से 17 हजार रुपये का है। इस कारण से अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में एयर इंडिया के माध्यम से टूरिस्ट्स नहीं आ रहे हैं। टिकट्स होते हुए भी टिकट्स ब्लैक हो रहे हैं। वहां दो सैक्टर्स में ऐसा हो रहा है - कोलकाता-पोर्टब्लेयर, चेन्नई-पोर्टब्लेयर। मैं एग्जाम्पल कोट करना चाहता हूं, 21 जून को मैं सफदरजंग में गया, वहां ...(व्यवधान) *

सभापति महोदय : आप उनका नाम मत लीजिए।

श्री विष्णु पद राय : मैंने उनसे रिक्वैस्ट की थी कि हमारे कम्पेनियन चेन्नई से पोर्टब्लेयर आये, उन्होंने एस.एम.एस. किया, बात की, लेकिन कहा गया कि टिकट नहीं है। 21 जून और 22 जून दो दिन में चार-चार टिकट चेन्नई एयरपोर्ट से बेचे गये।

सभापति महोदय : इसमें से नाम निकाल दीजिए।

श्री विष्णु पद राय : अजीब बात है कि 22 तारीख की फ्लाइट में चार-चार सीटें 1सी, 1डी, 2एफ. और 10ई आईं, वहां टिकट होते हुए ब्लैक चल रहा है। इसमें सबसे बुरी बात यह है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार के समय वहां वीकली दो-तीन स्ट्रेचर पेशेन्ट होते हैं, जैसे कोई कोमा में चला गया, किसी का सिर फट गया, उसे ट्रीटमैन्ट के लिए साउथ ग्रुप में जाना पड़ेगा। मैं 1999 में एम.पी. था,

---

* Not recorded

तब स्ट्रेचर पेशेन्ट्स के लिए 6 टिकट थे, जो एक टिकट कर दिया। उसकी कीमत 6 से 8 हजार रुपये कर दी। यूपीए सरकार आई, उसने दोबारा 6 टिकट कर दिए। लेकिन आज उसकी कीमत 90 हजार रुपये है। पेशेन्ट स्ट्रेचर में हैं, वह 90 हजार रुपये टिकट के देगा तो इलाज कहां से करेगा। उसे देखते हुए किंगफिशर ने अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में अपना लूटने का तरीका शुरू कर दिया। उन्होंने नौ टिकट कर दिये, जिसकी कीमत 1 लाख 82 हजार रुपये है।

सभापति महोदय : आप अपनी डिमांड बताइये।

श्री विष्णु पद राय : मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर से मांग करता हूं कि अंडमान निकोबार द्वीपसमूह का जो कोटा चेन्नई से पोर्टब्लेयर, कोलकाता-पोर्टब्लेयर उसे रिस्टोर करे और सस्ते दामों पर टिकट दे, जो दिल्ली, कोलकाता में चल रहा है, उसे देखते हुए हमारे यहां के टूरिज्म को बचाये और स्ट्रेचर पेशेन्ट के लिए सिंगल टिकट जो वाजपेयी सरकार ने किया था, वह अंडमान निकोबार के लिए करे।

श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर (परभणी): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान भारतीयों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले एक विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अमरीका की एक बीयर कंपनी ने बीयर की एक ब्रांड की बोतल के ऊपर गणेश जी का चित्र छापा है, जिसकी वजह से भारतीयों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। इसलिए अमरीकन कंपनी की बीयर की बोतल के ऊपर हिंदुओं के आराध्य देव गणेश जी की जो तस्वीर छापी गई है, वह दुनिया भर में हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है।

इसलिए मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि हिंदुओं के आराध्य गणपति बाबा का चित्र बीयर की बोतल पर छापने वाली कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सके, इस ढंग से सरकार को इस तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): This is a very serious matter which I am raising in this House during this late hour. The matter relates to Madras High Court where an hon. Judge has disclosed that a Union Minister had tried to influence him in granting anticipatory bail to two persons. This is a grave offence and it needs a thorough probe to ferret out the truth. As the Chief Justice of Supreme Court of India has left it to the Government to look into the matter, I urge upon the Government to state what step is being taken in this regard. The Prime Minister's credentials are above board. But can he be unmindful of the fact that a slur on the Government cannot but be seen as a slur on its Minister?